दयालबाग़ एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट एवं एम.एस.एम.ई.मंत्रालय द्वारा संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का प्रशिक्षणार्थियों के कौशलात्मक विकास, व्यावसायिक सफलता एवं आत्म–सम्प्रत्य के सन्दर्भ में एक तुलनात्मक अनुवर्ती अध्ययन

दयालबाग़ एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट की
डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (शिक्षा) उपाधि की पूर्ति
के निमित्त प्रस्तुत शोध

अध्ययन की रूपरेखा

2015

शोध निर्देशिका

डॉ0 गुरप्यारी सतसंगी
(एसोसिएट प्रोफेसर)
डिपार्टमेंट ऑफ पेडागॉजिकल साइंसिस

शोधार्थी

प्रियंका कुमारी

प्रो0 विभा निगम

विभागाध्यक्ष एवं संकाय प्रमुख
डिपार्टमेंट ऑफ पेडागॉजिकल साइंसिस
शिक्षा–संकाय

शिक्षा–संकाय
दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट (डीम्ड यूनिवर्सिटी)
दयालबाग, आगरा

1.0.0 प्रस्तावना

भारत में बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है। हमारे देश का मुख्य उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार एवं दरिद्रता की समस्या का समाधान करना है। शिक्षा के विकास के साथ–साथ बेरोजगारों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। हमारे देश की अधिकतम जनता गांवो में निवास करती है तथा कृषि एवं उद्योग धन्धों पर निर्भर करती है। इसलिए सबसे पहले हमें ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए जो व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर सके तथा उनका चहुँमुखी विकास कर सके।

हमारे देश में अभी तक पूर्ण औद्योगिक विकास नही हो सका है क्योकि हमारे पास प्राकृतिक संसाधन तो है परन्तु उनका पूरा–पूरा लाभ नहीं उठाया जा रहा है। तकनीक की हमारे देश में कमी है। शिक्षा का व्यावसायीकरण करने से विद्यार्थियों को व्यावसाय मिल जाता है इसलिए देश में उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से व्यावसायीकरण आवश्यक है। इससे देश की आर्थिक दशा सुधरेगी और कई आर्थिक समस्याओं का समाधान भी हो सकेगा।

मनुष्य को वास्तविक आनन्द तब प्राप्त होता है, जब उसे मन–पसन्द व्यवसाय मिल जाता है। शिक्षा को उपयोगी बनाने के लिए व्यावसायीकरण अति आवश्यक है। व्यावसायीकरण, शिक्षा प्रक्रिया को एक महत्वपूर्ण दिशा दे सकता है जिससे शिक्षा व्यवहारिक रूप से विद्यार्थियों के लिए उपयोगी बन सकती है। प्रचलित शिक्षा की दशा यह है कि शिक्षा अधिकतर पुस्तकीय होने के कारण जीवन की वास्तविकताओं से कटी हुई है। कक्षा में विद्यार्थियों को निष्क्रिय रूप से अध्यापको की ओर देखते या पुस्तकों को रट कर परीक्षा की तैयारी करते देख कर ऐसा लगता है कि शिक्षा उद्देश्यहीन है। शिक्षा का व्यावसायीकरण विद्यार्थियों को सक्रिय बनाकर शिक्षा को सार्थक एवं उद्देश्यपूर्ण बनाता है।

आज भारतीय समाज का ढांचा तेज गति से बदल रहा है। प्राचीन काल में व्यावसाय जाति के साथ जुड़े हुए थे और नव युवक पुश्तैनी कार्य में विशेष रूचि लेते थे। समय व सामाजिक परिवर्तनों के साथ लोगों की चिन्तनधारा में क्रान्तिकारी बदलाव आ रहे है। आज व्यावसायों का मूल्यांकन आर्थिक आधार

पर किया जाता है। कोई भी व्यावसाय, यदि उसमें धन का उपार्जन अधिक है तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी है तथा नवयुवकों की भीड़ उन व्यावसायों की ओर ही बढ़ रही है।

स्वतन्त्रता के बाद भारत के आर्थिक विकास का आधार पश्चिमी देशों के आधुनिकिरण को बनाया गया है। परिणामस्वरूप औद्योगिक क्रान्ति के कारण देश में अनेक नवीन व्यवसाय जन्म ले रहे है। इन व्यावसायों में विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। व्यावसायों मे इतने अवसर बढ़े हैं कि आज नवयुवको को तथा विशेषतः ग्रामीण युवको को इन नवोविकसित व्यावसायों का कोई ज्ञान नही है। हमारे देश के विद्यालयों में विद्यार्थीयों को इन व्यावसायों से परिचय कराने की कोई व्यवस्था नही है। आज यह मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है व देश में विकसित होने वाले व्यावसायों का गहन अध्ययन करके उनका ज्ञान विद्यार्थियों को करवाया जा रहा है।

व्यवसाय को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है– कार्य और व्यावसाय व्यक्ति के सामाजिक स्तर, मूल्य, अभिवृत्ति तथा जीवन मापन की शैली को निर्धारित करने वाले तत्व हैं लेकिन स्वयं ये सभी तत्व अंश रूप में व्यावसाय द्वारा निश्चित होते हैं। व्यवसाय केवल जीविकोपार्जन का साधन ही नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका, एक सामाजिक कृत्य भी हैं।

व्यवसायिक एवं कौशल परक शिक्षा के सन्दर्भ में प्रमुख आयोगों ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं–

हण्टर आयोग (1882) जिसे भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। 1882 ई. में इसकी स्थापना हुई। इस आयोग का सुझाव था कि शिक्षा में दो प्रकार के कोर्सों की व्यवस्था की जाए। एक कोर्स विश्वविद्यालय की शिक्षा की ओर अग्रसर करे और दूसरा कोर्स कौशल परक एवं अन्य व्यवसायों पर आधारित हो।

हार्टांग कमेटी (1929) ने शिक्षा के पाठ्यक्रम में औद्योगिक एवं वाणिज्य सम्बन्धी विषय सम्मिलित करने का सुझाव दिया था ताकि मैट्रिकुलेशन परीक्षा मे असफल होने वाले बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों पर धन, समय और मानव शक्ति का अपव्यय रूक जाय। परन्तु इस सुझाव की ओर भी कोई विशेष ध्यान नही दिया गया।

सपरू कमेटी (1934) उत्तर प्रदेश सरकार ने, बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन करने के लिए 1934 ई. में सपरू कमेटी की स्थापना की । इस कमेटी ने बेरोजगारी की समस्या के लिए शिक्षा को दोषी ठहराया क्योंकि हमारी शिक्षा में व्यवसायिक शिक्षा का अभाव था। इस समस्या के समाधान हेतु शिक्षा में सामान्य कोर्सों के साथ–साथ व्यावसायिक कोर्सों की व्यवस्था करने का सुझाव दिया था परन्तु इन सिफारिशों को लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए।

एवट–वुड रिपोर्ट (1936–37) में कहा गया है कि सामान्य शिक्षा देने वाली संस्थाओं के क्रमानुसार व्यावसायिक संस्थाएं स्थापित की जानी चाहिए। इसके परिणामस्वरूप कई बहु तकनीकी वाणिज्य तथा कृषि स्कूलों की स्थापना की गई।

सारजैण्ट रिपोर्ट (1944) में भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार सर सारजैण्ट ने 1944 ई. में शिक्षा के व्यवसायीकरण के सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं कि विद्यालयी संस्थानों में प्रवेश लेने वाले अधिकांश विद्यार्थियों को ऐसी दिशा प्रदान करनी चाहिए, जो उन्हे विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश करने की योग्यता प्रदान करे। विद्यालय संस्थान दो प्रकार के होने चाहिए– एक शैक्षणिक स्कूल और दूसरे तकनीकी स्कूल। शैक्षणिक स्कूलो में कलाओं एवं विशुद्ध विज्ञानों की शिक्षा दी जानी चाहिए और तकनीकि स्कूलों मे व्यावहारिक विज्ञान, उद्योगों तथा वाणिज्य की शिक्षा दी जानी चाहिए।

कोठारी आयोग (1964–66) के अनुसार इस समय भारत के भाग्य का निर्माण उसके अध्ययन कक्षों में हो रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित आज के विश्व में शिक्षा ही व्यक्तियों की समानता समृद्धि एवं सुरक्षा के स्तर को निश्चित करती है। कोठारी आयोग ने कहा कि तकनीकी कॉलेजों तथा जूनियर टैकनिकल कॉलेजों द्वारा छात्रों को उद्योगों में नौकरी के लिए तैयार करना चाहिए। कोर्स की अवधि कोर्स के अनुरूप होनी चाहिए इस प्रकार के कोर्सो में वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित प्रयोगात्मक कार्यो पर अधिक बल देना चाहिए। कोठारी आयोग ने छात्रों के लिए कृषि शिक्षा एवं अल्पकालीन शिक्षा की व्यवस्था करने की सिफारिश की है। जो विद्यार्थी अपने पारिवारिक खेती के काम में जाना चाहते है, उन्हें ग्रामीण स्कूलों में अपनी व्यावसायिक कुशलता को बढावा देने तथा साधारण शिक्षा देने के लिए

शिक्षा का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। उनका यह भी मानना है कि कला कौशल केन्द्रों में पूर्णकालीन पाठ्यक्रमों की सुविधाऐं प्रदान की जानी चाहिए एवं उद्योगों में अल्पकालीन, पूर्णकालीन एवं व्यवसायिक शिक्षा की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53) ने तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए केन्द्रीय तकनीकी संस्थाऐं स्थापित करने का सुझाव दिया। तकनीकी संस्थाऐं सम्बन्धित उद्योगों के निकट स्थापित की जाये तथा तकनीकी शिक्षा की कुशल योजना के लिए शिक्षा शास्त्रियों को उद्योग एवं वाणिज्य के विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त करना चाहिए एवं तकनीकी विकास में आने वाले व्यय को पूरा करने के लिए औद्योगिक शिक्षा कर लगाना चाहिए। जिससे पर्याप्त संख्या में औद्योगिक स्कूल स्थापित किए जा सकेंगे एवं तकनीकी कोर्सों की उचित प्रणाली निर्धारित करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की भी स्थापना करनी चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में कहा गया है कि व्यावसायीकरण के कार्यक्रम को रोजगार की सुविधाओं से जोड़ा जाना चाहिए शिक्षा का समन्वय एक ओर तो प्रशिक्षण तथा दूसरी ओर आर्थिक विकास के साथ स्थापित किया जाना चाहिए। औद्योगिक केन्द्रों में +2 की शिक्षा के पश्चात् महाविद्यालय की +3 की शिक्षा होगी। इस अवस्था पर पाठ्यक्रम को व्यक्ति और राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार विस्तृत एवं गहन कर दिया जाएगा।

एम.एस.एम.ई. का विस्तृत रूप सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (Micro, small & Medium Enterprises) हैं। जो कि केन्द्र सरकार के अधीन है। यह मन्त्रालय निर्माण भवन नई दिल्ली में स्थित है तथा यह केन्द्रिय मंत्रालयों में से व्यावसाय एवं रोजगारपरक प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। जो कि कृषि के बाद रोजगार का सबसे बडा हिस्सा प्रदान करता है यह मंत्रालय उद्ययमशीलता व नवीनता के लिए नर्सरी का कार्य करता है। इस मंत्रालय के कार्यालय प्रत्येक शहर में अवस्थित हैं। प्रस्तुत शोध अध्ययन में एम.एस.एम.ई. विकास संस्थान, आगरा को सम्मिलित किया जाएगा।

एम.एस.एम.ई. देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 8 प्रतिशत का योगदान देते हैं। जिसमें से उत्पाद में 45 प्रतिशत तथा निर्यात में 40 प्रतिशत योगदान देते हैं कृषि के बाद यह एक महत्वपूर्ण संस्था हैं, जो बडे पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराती है। एम.एस.एम.ई. देशभर में फैले 360 लाख उद्यमों के माध्यम से खास तौर पर कमजोर तबकों के लोगों को रोजगार और अल्पसंख्यको के साथ करीब 800 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहीं है, एम.एस.एम.ई. उद्यम क्षेत्रों और नये प्रचलनों के विकास केन्द्रो के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जो स्थानीय बाजारों के अलावा वैश्विक बाजारो, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मूल्य श्रृंखला की जरूरतों को पूरा करने के लिए सेवाओं तथा उत्पादों की लम्बी श्रृंखला मुहैया कराते हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए मूलभूत ढ़ांचा की सुविधाएं और सहायता सेवाएं मुहैया कराने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं और नीतियों का कार्यान्वयन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास, आयुक्त के कार्यालय के साथ ही खादी विलेज इन्ड्रस्टी कमीशन (केवीआईसी), कॉयर बोर्ड, नेशनल स्मॉल इन्ड्रस्टीज कॉपरेशन (एनएसआईस), इण्डियन इन्ड्रस्टी ऑफ एन्टरप्रीन्योरशिप (आईआईई), के माध्यम से किया जाता है।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एम.एस.एम.ई.) देशभर में समृद्धि को बढाने वाली प्रमुख इकाइयों की सहायता करने के लिए सभी राज्य सरकारों, औद्योगिक संगठनों, बैंको तथा अन्य संगठनों से अपने विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों और तकनीकी संस्थाओं के माध्यम से काफी समीप से समन्वय स्थापित करती हैं। खादी ग्राम और कॉयर उद्योगों ने कम लागत पर रोजगार निर्मित करने के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया है। खादी क्षेत्र को अधिकाधिक आकर्षक बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अधिकाधिक मजबूत बनाने के लिए ही खादी विलेज इन्ड्रस्टी कमीशन (केवीआईसी) ने सुधारों के साथ ही खादी व अन्य तबके के कार्यो को अंजाम दिया गया है। कॉयर (नारियल की जटाएं) उद्योग कृषि आधारित सबसे पुराने पारम्परिक उद्यमों में से एक है जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते है और हर साल करीब 800 करोड रूपये का निर्यात किया जाता है। इसकी

पर्यावरणानुकूल छवि के कारण इसकी तकनीकी सुधारों के आधार पर मूल्यवर्धित विभिन्न तरह के उत्पाद देश पर निर्यात बढाने की भी अपार सम्भावनाएं है। खादी ग्राम और कायर क्षेत्र के उद्योग समूहों को विकसित करने के लिए 'स्कीम ऑफ फन्ड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशन इड्रस्ट्रीज नामक एक अन्य पहल की गई है स्फूर्ति योजना के अन्तर्गत अब तक 101 उद्योग समूहों का विकास किया गया है जिनमें खादी के 29, ग्रामोद्योग के 47 तथा कायर बोर्ड के 25 उद्योग समूह शामिल है एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना में 800 समूह के विकास का प्रस्ताव रखा गया है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम इस मंत्रालय की एक प्रतिष्ठित योजना है। जबकि खादी विलेज इन्ड्रस्टी कमीशन (केवीआईसी) ने करीब 2.74 लाख इकाईयों के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध करा कर इस दिशा में अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया है जबकि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 3.39 लाख परियोजनाओं की स्थापना कर करीब 27.12 लाख लोगों को रोजगार के अवसर का प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2013–2014 के दौरान 50460 इकाइयों के लिए करीब 1075. 55 करोड रूपये की अतिरिक्त रियायत निधि से लगभग 3.68 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया करने का प्रयास किया गया । राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की ओर से देश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के अलावा लघु उद्योगो के विकास को लिए प्रोत्साहन व सहायता प्रदान करने और उनकी देखभाल करने का प्रयास किया गया है। परिवर्तन समृद्धि और विकास की 50 वर्षो की इस यात्रा के दौरान नेशनल स्मॉल इन्ड्रस्टीज कॉपरेशन (एनएसआईसी) ने आधुनिक तकनीकि के उन्नतिकरण व गुणवत्ता के बारे में मध्यम उद्यमों के साथ उनके सम्बन्धों को मजबूत बनाने और लघु उद्यम उत्पादन के निर्यात में वृद्धि कर भारत में ही नही विदेशों में भी अपनी क्षमता सिद्ध कर दी है।

वर्तमान में तेजी से बदलते आर्थिक और औद्योगिक परिदृश्य में तकनीकी का महत्व पहले से कही अधिक बढ़ गया है। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए तकनीकी विकास और उसको अंगीकार करना आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण आधार बन गया है। भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 18 तकनीकी केन्द्रों की स्थापना की है। इसके अलावा देशभर में 15 अन्य केंन्द्रो की

स्थापना इस वर्ष के दौरान की जा रही है जिससे स्कूली पढाई अधूरी छोड़ चुके युवाओं को भी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और तकनीकी सेवाएं प्रदान की जा सके। इसके अलावा एमएसएम.ई मंत्रालय की सीडीपी योजना (केंरेक्ट्रीस्टिक डीपेन्डेन्ट प्लानिगं) के अन्तर्गत मूलभूत ढांचे के विकास के लिए 170 परियोजनाएं शुरू की गई है। उद्योगों के लिए निपुण मानव संसाधन की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए युवाओं में उद्यमिता विकास एवं निपुणता विकास के लिए परिपूर्ण जनमत प्राप्त करने वाले सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा वर्ष 2010 मे प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता योजना का संचालन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन राष्ट्रीय स्तर के तीन उद्यमिता संस्थानों की ओर से किया जा रहा है। इन परियोजना का लाभ देशभर के करीब 3.5 लाख बेरोजगार युवाओं को दिया जा चुका है। इस योजना को उद्योगों की स्थापना के मामले में 26 प्रतिशत, जबकि वेतन रूपी रोजगार मुहैया कराने के मामले में 55 प्रतिशत सफलता प्राप्त हुई है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मन्त्रालय की नई पहल वर्चुअल समूह है, जो भौतिक उद्योग समुहों के लिए पूरक है।

राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने गत 9 जून 2015 को संसद में खासतौर पर बताया कि उत्पादन क्षेत्र में रोजगार के अवसरो का बडे पैमाने पर सृजन करने के लिए सरकार योजनाबद्ध तरीके से उत्पादन को प्रोत्साहन देगी। पर्यटन एवं कृषि आधरित उद्योगो को प्रेत्साहन देकर ही रोजगाार के अवसरों को बढ़ाया जा सकता है। विद्यार्थियो को हस्त कला क्षेत्र के साथ सूक्ष्म और मध्यम उद्यमो को अन्य प्रैद्योगिकी निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराकर प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा।

सरकार ने हाल ही मैं धोषित आम बजट (2014–2015) में खास तौर पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की है जैसे 10 हजार करोड रूपये स्किल इंडिया कार्यक्रम की शुरूआत करने में खर्च किए। इन कार्यक्रमो में लोग हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित करने तथा बढावा देने की सीख लेगें। जिससे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के विकास के लिए कार्य योजना बनाने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा उन्होने रोजगार मार्गदर्शन कार्यालयो को केरियर केन्द्रों में परिवर्तीत

करने की घोषणा की है। जिससे युवाओं के प्रौद्योगिक परामर्श को रोजगाार के अवसरो के साथ जोड़ा जा सके।

उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थी लम्बे समय तक कॉलेजों मे रहते है जिसके कारण रोजगारो में जाने का प्रतिशत घटा है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए तो लोगों को नये रोजगार चलाने में सहायक हों व जो नये उद्यमियों को जन्म दे सके। विद्यार्थियो की सफलता हेतु आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध करा सके। वर्तमान शिक्षा प्रणाली ज्यादातर विद्याथियों को पेशेवर व विशेषज्ञ तो बनाते है, परन्तु उनका ध्यान विद्यार्थियो को उद्यमी बनाने की ओर नही होता है। शिक्षा संस्थान व्यावसायिक व पेशेवर संगठनों से हाथ मिलाकर सरकार इस काम को बेहतर अंजाम दे सकती है। शिक्षा संस्थान के द्वारा विद्याथियो को उद्यमी बनने की शिक्षा एवं प्रेरणा नही दी जाती है। यदि शिक्षण संस्थान अपना दृष्टिकोण बदले तो विद्यार्थी भी अपने सोचने का तरीका बदलेगे तथा ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी उद्यमी बनने के विकल्प की ओर आकर्षित होंगे ।

दयालबाग एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट (डी.ई.आई.) आगरा शहर के दयालबाग में स्थित एक शिक्षण संस्थान है। इस संस्थान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा सन् 1981 में डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में दर्जा दिया गया । वर्तमान में इस संस्थान के निदेशक प्रो. प्रेम कुमार कालरा हैं।

सर्वप्रथम डी.ई.आई. को सन् 1917 में प्राथमिक स्कूल के रूप में स्थापित किया गया । ऑटोमोबाईल, इलैक्ट्रिकल और मकैनिकल इंजीनियरिंग के प्रशिक्षण के लिए सन् 1927 में यह एक तकनीकी कॉलेज के रूप में विकसित हुआ बाद में यह एक डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। प्रो. एम.बी. लाल साहब इस संस्थान के प्रथम निदेशक थे तथा उन्होंने ही इस संस्था की नींव रखी । सन् 1981 के बाद से विश्वविद्यालय ने सफलता पूर्वक व्यापक, नवीन एवं मूल्य आधारित शिक्षा पर जोर देते हुए शैक्षिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र की गुणवत्ता व उत्कृष्टता को बनाए रखने में प्रयासरत है। डी.ई.आई. ने अपने शैक्षिक एवं व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोर पाठ्यक्रमों व सह पाठ्यक्रमों की गतिविधियों को सम्मिलित किया है। हाल ही में डी.ई.आई को एम.एच.आर.डी. की एक उच्चाधिकार

प्राप्त समिति ने भारत के 126 डीम्ड विश्वविद्यालयों में से डी.ई.आई. को 8वां स्थान प्रदान किया है। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय में अनेको शैक्षिक एवं व्यावसायिक रोजगारपरक पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री की दीनदयाल उपाध्याय कौशल सेन्टर योजना के तहत देश भर में व्यावसायिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत हाल ही में देशभर में करीब 708 व उत्तरप्रदेश में 43 विश्वविद्यालयों ने प्रस्ताव भेजे थे जिसमें उत्तरप्रदेश में से तीन विश्वविद्यालयों के प्रस्ताव स्वीकृत किए जिसमें सबसे अधिक धनराशि 4.90 करोड़ दयालबाग एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट (डी.ई.आई.) को मिली है। इसके बाद नेशनल पी. जी. कॉलेज, लखनऊ को 4.65 करोड़ तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को 3. 65 करोड़ रूपये मिले है। वोकेशनल कोर्सेज के माध्यम से केन्द्र सरकार छात्रों को अधिक से अधिक रोजगार प्रदान करना चाहती है। इसलिए दीनदयाल उपाध्याय कौशल सेन्टर योजना के तहत देशभर के विश्वविद्यालयों में वोकेशनल कोर्सेज खोले जाने है। इस योजना के तहत विश्वविद्यालयों में कम्यूनिटी कॉलेज व वोकेशनल डिग्री कार्स शुरू किए जाते हैं। पहले यह योजना नॉलेज अपग्रेडेशन फॉर स्किल्ड ह्यूमन एक्शन एण्ड लर्निंग के नाम से चल रही थी। लेकिन मोदी सरकार ने इसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय नॉलेज एक्वीजनिशन एण्ड अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्ड ह्यूमन एबिलिटीज एण्ड लाइव हुड कर दिया इसके तहत पहले बजट में सौ कौशल विकास सेन्टर की घोषणा की गयी है।

अतः प्रस्तुत अध्ययन में एम.एस.एम.ई. एव डी.ई.आई. के द्वारा क्रियान्वित रोजगाार एवं कौशल परक कार्यक्रमों का मूल्यांकन प्रशिक्षणार्थियों की व्यावसायिक सफलता, आत्म सम्प्रत्यय एवं कौशलात्मक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में किया जाएगा।

1.2.0 समस्या का प्रादुर्भाव एवं औचित्य

आज पूरा विश्व युवा कौशल दिवस मना रहा है भारत भी इस अवसर पर एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है और हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी की हर परिचर्चा में स्किल इंण्डिया का जिक्र किया जाता

है। उनका तर्क है कि देश का कोई नौजवान हाथ फैलाकर कुछ माँगने को मजबूर न हो, वो दयनीय जिंदगी न जियें, वो आत्म सम्मान और गर्व के साथ जीवन जी सकें। कौशल, कौशल्य और सामर्थ्य ये सिर्फ जेब भरने के लिए नहीं या केवल रूपया कमाने के लिए नही हैं। ये जीवन में आत्मविश्वास की एक नयी रोशनी की किरण लाते हैं और एक नयी ताकत का उदय होता है। इसलिए विश्व के पटल पर कौशल विकास एक महत्वपूर्ण एजेंण्डा है।

स्किल इंण्डिया के एजेंण्डा को प्राप्त करने के लिए एम.एस.एम.ई. मंत्रालय व डी.ई.आई. संस्थान विभिन्न कौशल विकास एवं रोजगार परक पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है। इन कार्यक्रमों का प्रशिक्षणार्थियों के कौशलात्मक विकास, व्यवसायिक सफलता एवं उनके व्यवसायिक आत्मसम्प्रत्यय के सन्दर्भ में मूल्याकंन करना अति आवश्यक है। प्रस्तुत शोध में शोधार्थी ने एक अनुवर्ती शोध अध्ययन पर बल दिया है। जिससे कौशल विकास एवं रोजगार परक कार्यक्रमों की उपलब्धियों का मूल्याकंन किया जा सके।

व्यावसायिक एवं कौशल परक शिक्षा के सन्दर्भ में विभिन्न अनुसन्धान कार्य किए गए हैं जैसे–

वीना (2015) ''रोल आफ डवलपमेन्ट इन्स्टीट्यूट इन द इस्टेब्लीस्मेन्ट ऑफ माइक्रो स्मॉल एण्ड मीडियम एन्टरप्राइस : अ केस स्टडी ऑफ भवानी हरियाणा'' में पाया गया एम.एस.एम.ई विकास संस्थान के परामर्श और कार्यक्रम बहुत प्रभावी पाये गये। लोगो को इस ओर अधिक प्रोत्साहित करके उन्हें सशक्त का सकते हैं।

आशु कात्याल एवं विट्से एक्सविअर (2015)''अ स्टडी आन एम.एस.एम.ई. रोल इन प्रोपलिंग इकॉनोमिक डवलपमेन्ट ऑफ करेन्ट एच. आर. इशु इन एम.एस.एम.ई. इन इण्डिया'' में बताया गया है कि एम.एस.एम.ई. मानव संसाधन संगठनों के लिए आज सबसे जरूरी विकास संकेतकों में से एक है। आज मानव संसाधन के प्रबन्धन की औपचारिकता में कमी नहीं है। इस हेतु संरचित और औपचारिक मानव संसाधन प्रणाली को अपनाया है। मानव संसाधन में एम.एस.एम.ई के कौशल युक्त प्रशिक्षण कार्यो से उसके महत्व को स्वतः ही समझा जा सकता है।

सुरत कुमार दास (2014) ''ग्रोथ एण्ड प्रोस्पेक्ट आफ एम.एस.एम.ई. इन ओडिशाः एन एनालिटिकल एप्रोच'' में बताया गया है कि निष्कर्ष रूप में पाया गया कि ओड़िसा में एम.एस.एम.ई. के द्वारा विकास दर में बहुत प्रगति हुई है व इसके द्वारा सामाजिक आर्थिक विकास हुआ है।

रूपाली शर्मा एवं ज़िया अफरोज (2014) ''ग्रोथ एण्ड परफोरमेन्स ऑफ एम.एस.एम.ई. इन प्रजेन्ट सिनेरियो फॉर द डवलपमेन्ट ऑफ इण्डिया'' में निष्कर्ष रूप में बताया गया है कि एम.एस.एम.ई. घरेलू अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में बड़ा योगदान हैं। इसके विकास के लिए सरकार के द्वारा पर्याप्त अनुदान व समर्थन प्रदान किया जाता है।

नेहा ड़ागी एवं रीतिका (2014) ''वुमेन इन्टर्नशिप ग्रोथ एण्ड एम.एस.एम.ई. इन इण्डिया '' में पाया गया कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय आर्थिक वृद्धि एवं विकास में योगदान कर रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की सफलता हेतु एम.एस.एम.ई. में महिला उद्यमियों के लिए नये रास्ते खोले गये। जिससे भारत में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन व्यतीत कर सकती है।

सिंह एवं रैना (2013) ''वुमेन एन्टरप्रीन्योर इन माइक्रो स्माल एण्ड मीडियम एन्टरप्राईज '' में बताया गया कि भारत में महिला उद्यमियों को अनेक समस्याओं एवं चुनौतियों का सामना करना पडता है। प्रस्तुत अध्ययन में बताया गया है कि आधुनिक भारत में अधिक से अधिक महिलाओं को विशेष उद्यमों में रोजगार प्राप्त है। भारत पुरूष प्रधान देश है वहा महिलाए पुरूषो के बराबर भारतीय उद्यमों में कार्यरत हैं।

श्रीनिवास एवं अन्य (2013) ''सस्टेनेबल ट्रेन्डस एण्ड पोलिसी ऑफ एम.एस.एम.ई. इन इकॉनोमिक डवलपमेन्ट इन इण्डिया : एन इम्पेरिकल स्टडी'' में बताया गया है कि एम.एस.एम.ई. उद्ययम का गठन भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके द्वारा उत्पादन प्रणाली के क्षेत्र में रोजगार सृजन, सकल घरेलू उत्पाद में नवाचार व रचनात्मकता की योग्यता रखता है। देश में सक्षम औद्योगिक विकास के व्यापक लक्ष्य को एम.एस.एम.ई. द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। इसके द्वारा आर्थिक विकास के हर पहलू पर विचार किया जाना चाहिए।

जयन (2013) वुमेन इन्टरप्रीन्योशिप इन एम.एस.एम.ई.(विद् स्पेशल रिंन्स टू कोयम्बटूर सिटी) में महिलाओं का विश्लेषण किया है। इन्होने एम.एस.एम.ई. में उद्यमीयों की सफलता का कोयंबटूर शहर के सन्दर्भ में अध्ययन किया और अध्ययन में पाया कि महिलाओं को एक सफल उद्यमी बनने में उपलब्धि प्रेरणा और मानव सम्बन्ध प्रेरित करते है।

सुब्रमण्यम एवं रेड्डी (2012) ''माइक्रो स्मॉल एण्ड मिडियम एन्टरप्राइजिस प्रजेन्टिग एन ओवरव्यू'' में पाया गया कि एम.एस.एम.ई. द्वारा आर्थिक क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया गया है तथा एम.एस.एम.ई. भारत के सकल घरेलु उत्पाद व निर्यात के क्षेत्र पर अपनी निगाह बनाए हुए है।

सुधा वैंकटेश एवं क्रिश्नावेनी मुथैया (2012) ''एम.एस.एम.ई इन इण्डिया : इनपोटेन्स एण्ड कॉन्ट्रिब्यूशन'' एम.एस.एम.ई. की भूमिका से औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है। यह भविष्य में आर्थिक विकास हेतु एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया । भारतीय उद्योग विभिन्न क्षेत्रो में तेजी से प्रगति कर रहे है। एम.एस.एम. ई. के द्वारा भारतीय आर्थिक परिदृश्य बदल रहे हैं।

ईशु गर्ग (2012) ''एम.एस.एम.ई इम्प्रुवमेन्ट इन नार्थ इण्डियाः स्टेटस एण्ड परफोरमेन्स'' में बताया गया है कि एम.एस.एम.ई अर्थव्यवस्था में एक जीवन्त एवं गतिशील घटक के रूप में उभरा है। रोजगारी में कमी के कारण बेरोजगारी में वृद्धि हुई है जिससे अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है सरकार द्वारा प्रयास किये गये है कि बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए एम.एस.एम.ई. अपनी नीतियों का कार्यान्वयन कर रही है तथा भरतीय अर्थव्यवस्था में एम.एस.एम.ई. अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सिंह व अन्य (2012) '' लघु उद्योग : विकास का एक इंजन'' प्रस्तुत शोध अध्ययन में भारत में लघु उद्योगों के क्षेत्र में नये अवसर खोले गये हैं। तथा नीतियो में परिवर्तन पर ध्यान केद्रित किया गया है। निष्कर्ष रूप में पाया गया कि लघु उद्योगो क्षेत्र का इकाईयों ने उत्पादन व रोजगारो की संख्या में प्रगति हुई है। प्रौद्योगिक विकास और वित्तीय बुनियादी ढ़ाँचे को मजबूत बनाने व विकास दर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लघु उद्यमों को बढावा देना आवश्यक माना गया है।

कुमार एन. बी. गुगलोथ (2012) ''माइक्रो स्मॉल एण्ड मीडियम एन्टरप्राइसिस इन द 21 सेन्चुरी'' में उदारीकरण के बाद एम.एस.एम.ई का मूल्यांकन किया गया तथा एम.एस.एम.ई. के पहले व वैश्वीकरण के बाद एम.एस.एम.ई. के मुख्य मानदण्डों के विकास का तुलनात्मक विश्लेषण किया इस विश्लेषण के लिए 1999 से 2010 तक की अवधि को लिया गया है तथा इसमें कारोबारी माहौल में चल रहे परिवर्तनों पर ध्यान केद्रित किया गया व उदारीकरण का अवधि में लधु उद्योग क्षेत्र में विकास पिछले कुछ वर्षों में तेजी से हुआ है। एम.एस.एम.ई. ने क्षेत्र के विकास में तथा हमारी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।

दीक्षित एवं पांडेय (2011) ''भारत में एम.एस.एम.ई और आर्थिक विकास'' इसमें पाया गया है कि एम.एस. एम.ई से उत्पादन, निर्यात, रोजगार आदि की संख्या में वृद्धि हुई है जिससे विकास को नई दिशा प्राप्त हुई है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद व कुल निर्यात में 1973–74 से 2006–07 तक की अवधि में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में रोजगार वृद्धि देखी गयी है। अध्ययन में एम.एस.एम.ई. के उत्पादन और सकल घरेलू उत्पाद के बीच सकारात्मक सम्बन्ध पाया गया है।

धर्मकीर्ती जोशी, विद्या, व पूनम मुनजल (2010) ''स्किलिंग इण्डिया : द बिलिसन पीपुल्स चैलेन्ज'' में बताया गया है कि भारत को अपने आर्थिक विकास की चुनैतियों से निपटने के लिए युवा वर्ग को रोजगाार के अवसर दे व उनमें कौशलात्मक विकास को बढावा दिया जाये। भारत को अपनी नीतियों में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। जिससे सभी व्यक्ति हुनरमन्द हो सकें।

ग्वेंडोलिन आर. टेक्सन (2004) ''रीव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग पोलिसी अफेक्टिंग माइक्रो स्मॉल एण्ड मीडियम एन्टरप्राइस इन फिलिपिन्स'' में बताया गया है कि एम.एस.एम.ई के वातावरण से उसकी वृद्धि, विकास, योजनाओं, व कार्यक्रमो पर प्रभाव के कारण इसके विकास की बहुत कम गुंजाइश पायी गई।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि एम.एस.एम.ई का भारत के आर्थिक विकास में योगदान, एम. एस.एम.ई. की गुणवत्ता एवं क्रियान्वयन, एम.एस.एम.ई का महिला सशक्तिकरण में योगदान एवं कौशलात्मक विकास में योगदान पर प्रमुख शोध हुए हैं। परन्तु प्रस्तुत शोध अध्ययन के सन्दर्भ में बहुत

कम शोध हुए हैं एवं एम.एस.एम.ई एवं डी.ई.आई जो कौशल परक कार्यक्रमो में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, के कार्यक्रमो का मूल्यांकन प्रशिक्षणार्थियो के कौशलात्मक विकास उनकी व्यवसायिक सफलता एवं आत्म सम्प्रत्यय के सन्दर्भ में किया जा रहा हैं प्रस्तुत शोध अध्ययन के विषय में प्रमुख शोध प्रश्न निम्ललिखित है। जिसकी खोज प्रस्तुत अध्ययन की सार्थकता की ओर इंगित करती है।

- क्या एम.एस.एम.ई. द्वारा संचालित रोजगाार परक एवं कौशल विकास कार्यक्रम प्रशिक्षणार्थियों के कौशलात्मक विकास के सन्दर्भ में प्रभावपूर्ण योगदान अदा कर रहे हैं?
- डी.ई.आई. जो रोजगार परक एवं कौशलात्मक विकास कार्यक्रमों को संचालित करने में एक नव प्रतिष्ठित संस्था है, क्या वह विद्यार्थियों के कौशलात्मक विकास के सन्दर्भ में प्रमुख भूमिका अदा कर रही है?
- क्या प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अर्जित कौशलो के सन्दर्भ में एम.एस.एम.ई अथवा डी.ई.आई. द्वारा संचालित पाठयक्रम अधिक प्रभावी है ?
- क्या एम.एस.एम.ई. द्वारा संचालित रोजगाार परक एवं कौशल विकास कार्यक्रम प्रशिक्षणार्थियों के व्यावसायिक सफलता के सन्दर्भ में प्रभावपूर्ण योगदान अदा कर रहे है?
- डी.ई.आई. जो रोजगार परक एवं कौशलात्मक विकास कार्यक्रमों को संचालित करने में एक नव प्रतिष्ठित संस्था है, क्या वह विद्यार्थियों की व्यावसायिक सफलता के सन्दर्भ में प्रमुख भूमिका अदा कर रही है?
- क्या प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अर्जित व्यावसायिक सफलता के सन्दर्भ में एम.एस.एम.ई अथवा डी.ई. आई. द्वारा संचालित पाठयक्रम अधिक प्रभावी है ?
- क्या एम.एस.एम.ई. द्वारा संचालित रोजगाार परक एवं कौशल विकास कार्यक्रम प्रशिक्षणार्थियो के व्यावसायिक आत्म सम्प्रत्यय के सन्दर्भ में प्रभावपूर्ण योगदान अदा कर रहे है?

- डी.ई.आई. जो रोजगार परक एवं कौशलात्मक विकास कार्यक्रमों को संचालित करने में एक नव प्रतिष्ठित संस्था है, क्या वह विद्यार्थियों के व्यावसायिक आत्म सम्प्रत्यय के सन्दर्भ में प्रमुख भूमिका अदा कर रही हैं?
- क्या प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अर्जित व्यावसायिक आत्म सम्प्रत्यय के सन्दर्भ में एम.एस.एम.ई अथवा डी.ई.आई. द्वारा संचालित पाठयक्रम अधिक प्रभावी हैं ?

अतः औद्योगिक भारत में उपरोक्त सार्थक शोध प्रश्नों की खोज के सन्दर्भ में शोधार्थी ने दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट एवं एम.एस.एम.ई. मंत्रालय द्वारा संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का प्रशिक्षणार्थियों के कौशलात्मक विकास, व्यावसायिक सफलता एवं आत्म–सम्प्रत्य के सन्दर्भ में एक तुलनात्मक अनुवर्ती अध्ययन पर शोध अध्ययन करने का निर्णय लिया है।

1.3.0. समस्या कथन

दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट एवं एम.एस.एम.ई. मंत्रालय द्वारा संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का प्रशिक्षणार्थियों के कौशलात्मक विकास, व्यावसायिक सफलता एवं आत्म–सम्प्रत्य के सन्दर्भ में एक तुलनात्मक अनुवर्ती अध्ययन।

1.4.0 समस्या में प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण

1.4.1. दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट

दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट, दयालबाग, आगरा में स्थित यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त एक शैक्षणिक संस्था है, जिसकी स्थापना 1981 में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में हुई। आज विश्व पटल पर इस विश्वविद्यालय द्वारा अनेकों कौशल विकास व रोजगार परक पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है।

1.4.2. एम.एस.एम.ई.

एम.एस.एम.ई. का विस्तृत रूप सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (Micro, small & Medium Enterprises) हैं। जो कि केन्द्र सरकार के अधीन है। यह मन्त्रालय निर्माण भवन, नई दिल्ली में स्थित है तथा यह केन्द्रिय मंत्रालयों में से व्यावसाय एवं रोजगारपरक प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। जो कि कृषि के बाद रोजगार का सबसे बडा हिस्सा प्रदान करता है यह मंत्रालय उद्यमशीलता व नवीनता के लिए नर्सरी का कार्य करता है। इस मंत्रालय के कार्यालय प्रत्येक शहर में अवस्थित हैं। प्रस्तुत शोध अध्ययन में एम.एस.एम.ई. विकास संस्थान, आगरा को सम्मिलित किया जाएगा।

1.4.3. व्यावसायिक सफलता

प्रस्तुत शोध अध्ययन में व्यावसायिक सफलता के अन्तर्गत लाभार्थियों के व्यावसायिक समायोजन, सन्तुष्टि, अनुकूलित वातावरण, वेतन, व सन्तुलित कार्यभार, आयामों के सन्दर्भ में मूल्यांकन किया जाएगा।

1.4.4. कौशलात्मक विकास

जब किसी प्रशिक्षणार्थीओं को जब किसी निश्चित कौशल के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है एवं प्रशिक्षणोपरान्त जब उनका मूल्याकंन किया जाता है तो उसकी उपलब्धि कौशलात्मक विकास की सीमा को दर्शाती है।

1.4.5. व्यवसायिक आत्म सम्प्रत्य

आत्मप्रत्यय एक आत्म स्कीमा या आत्म ज्ञान है जिसके माध्यम से वह स्वयं में विकसित व्यवसायिक कौशलों को आत्ममूल्यांकित कर सकता है। यह विशेषता उस व्यक्ति की आत्म सम्प्रत्यय के रूप में दर्शायी जाती है।

1.5.0 अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन हेतु निम्न उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं–

1 दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त महिला एवं पुरूष प्रशिक्षणार्थियों के कौशलात्मक विकास का अध्ययन ।

2. एम.एस.एम.ई. से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त महिला एवं पुरूष प्रशिक्षणार्थियों के कौशलात्मक विकास का अध्ययन।

3 दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट एवं एम.एस.एम.ई द्वारा संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का प्रशिक्षणार्थियों के कौशलात्मक विकास के सन्दर्भ में तुलनात्मक अध्ययन।

4 दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त महिला एवं पुरूष प्रशिक्षणार्थियों की व्यावसायिक सफलता का अध्ययन।

5 एम.एस.एम.ई. से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त महिला एवं पुरूष प्रशिक्षणार्थियों की व्यावसायिक सफलता का अध्ययन।

6 दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट एवं एम.एस.एम.ई द्वारा संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का प्रशिक्षणार्थियों की व्यावसायिक सफलता के सन्दर्भ में तुलनात्मक अध्ययन।

7 दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त महिला एवं पुरूष प्रशिक्षणार्थियों के आत्म सम्प्रत्यय का अध्ययन ।

8 एम.एस.एम.ई. से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त महिला एवं पुरूष प्रशिक्षणार्थियों के आत्म सम्प्रत्यय का अध्ययन ।

9 दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट एवं एम.एस.एम.ई द्वारा संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का प्रशिक्षणार्थियों के आत्म सम्प्रत्य के सन्दर्भ में तुलनात्मक अध्ययन।

10 दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट द्वारा संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का प्रशिक्षणार्थियों के कौशलात्मक विकास, व्यावसायिक सफलता एवं आत्मसम्प्रत्य के सन्दर्भ में स्वॉट (SWOT) विश्लेषण।

11 एम.एस.एम.ई. द्वारा संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का प्रशिक्षणार्थियों के कौशलात्मक विकास, व्यावसायिक सफलता एवं आत्मसम्प्रत्य के सन्दर्भ में स्वॉट (SWOT) विश्लेषण ।

12 दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट एवं एम.एस.एम.ई. द्वारा संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का प्रशिक्षणार्थियों के कौशलात्मक विकास, व्यावसायिक सफलता एवं आत्मसम्प्रत्य के सन्दर्भ में स्वॉट (SWOT) विश्लेषण का तुलनात्मक अध्ययन।

1.6.0 अध्ययन की परिकल्पनाएँ

प्रस्तुत अध्ययन में शून्य परिकल्पना का अनुसरण किया जाएगा–

1 दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीटयूट से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त महिला एवं पुरूष प्रशिक्षणार्थियों के कौशलात्मक विकास में कोई सार्थक अन्तर नहीं होना चाहिए।

2 एम.एस.एम.ई. से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त महिला एवं पुरूष प्रशिक्षणार्थियों के कौशलात्मक विकास में कोई सार्थक अन्तर नहीं होना चाहिए।

3 प्रशिक्षणार्थियों के कौशलात्मक विकास के सन्दर्भ में दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीटयूट एवं एम.एस. एम.ई. द्वारा संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रभावशीलता में कोई सार्थक अन्तर नहीं होना चाहिए।

4 दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीटयूट से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त महिला एवं पुरूष प्रशिक्षणार्थियों की व्यावसायिक सफलता में कोई सार्थक अन्तर नहीं होना चाहिए।

5 एम.एस.एम.ई. से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त महिला एवं पुरूष प्रशिक्षणार्थियों की व्यावसायिक सफलता में कोई सार्थक अन्तर नहीं होना चाहिए।

6 प्रशिक्षणार्थियों की व्यावसायिक सफलता के सन्दर्भ में दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीटयूट एवं एम.एस. एम.ई. द्वारा संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रभावशीलता में कोई सार्थक अन्तर नहीं होना चाहिए।

7 दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीटयूट् से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त महिला एवं पुरूष प्रशिक्षणार्थियों के आत्म सम्प्रत्यय में कोई सार्थक अन्तर नहीं होना चाहिए।

8 एम.एस.एम.ई. से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त महिला एवं पुरूष प्रशिक्षणार्थियों के आत्म सम्प्रत्यय में कोई सार्थक अन्तर नहीं होना चाहिए।

9 प्रशिक्षणार्थियों के आत्मसम्प्रत्यय के सन्दर्भ में दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीटयूट एवं एम.एस.एम.ई. द्वारा संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रभावशीलता में कोई सार्थक अन्तर नहीं होना चाहिए।

1.7.0 अध्ययन की विधि

वर्तमान अध्ययन के अन्तर्गत शोधार्थी द्वारा अनुसंधान की **वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि** एवं **अनुवर्ती शोध अध्ययन विधि** का अनुसरण किया जाएगा।

1.8.0 न्यादर्श प्रारूप

प्रस्तुत शोध अध्ययन के उददेश्यों को ध्यान में रखते हुए दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीटयूट, दयालबाग, आगरा एवं एम.एस.एम.ई.–विकास संस्थान, आगरा का ''सोद्देश्य न्यादर्श विधि'' द्वारा चयन किया जाएगा एवं उपरोक्त संस्थानों में व्यावसायिक प्रशिक्षणार्थियो का चयन ''स्नॉबाल न्यादर्श विधि'' द्वारा किया जाएगा। जिसमें दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीटयूट आगरा के 200 (100 महिला व 100 पुरूष) एवं एम. एस.एम.ई.–विकास संस्थान, आगरा के 200 (100 महिला व 100 पुरूष) का चयन किया जाएगा। इस प्रकार शोध अध्ययन हेतु कुल 400 (200 महिला व 200 पुरूष) व्यावसायिक प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जाएगा।

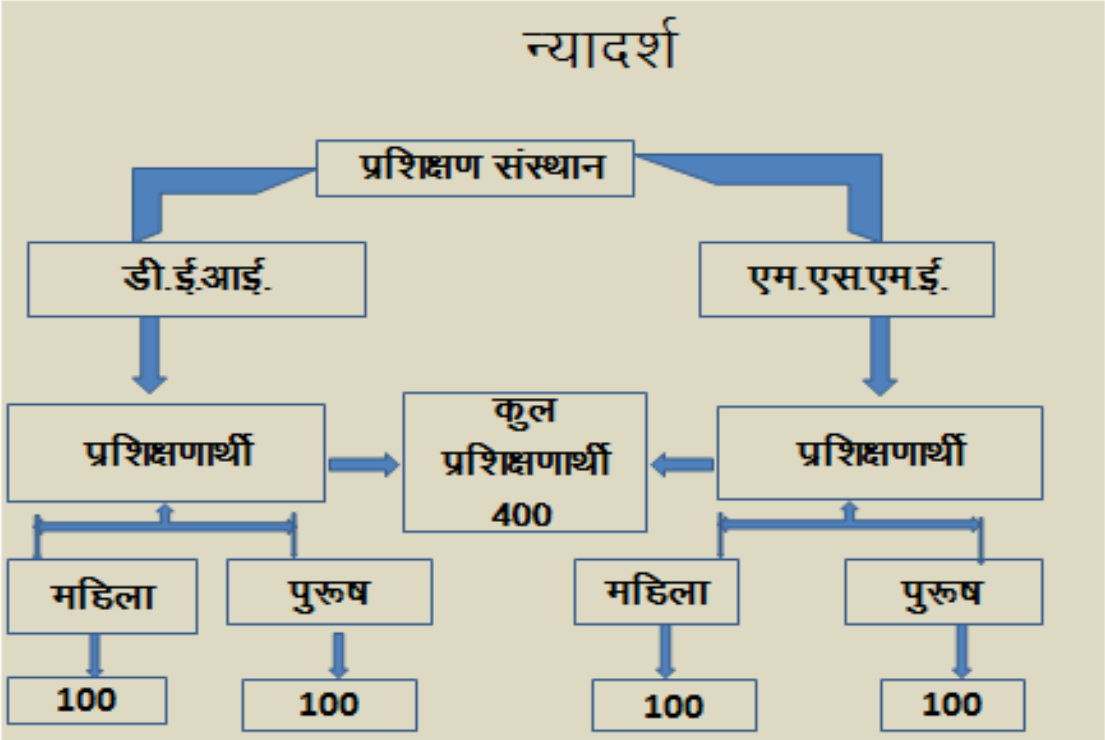

1.9.0 अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण

शोध अध्ययन हेतु शोधार्थी द्वारा निम्न उपकरणों का निर्माण किया जाएगा–

1 **कौशलात्मक विकास मापनी :–** प्रस्तुत अध्ययन में शोधार्थी, संस्थानों द्वारा संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा प्रशिक्षण में विकसित कौशलो के मापन हेतु स्व–निर्मित प्रश्नावली का निमार्ण करेगी।

2 व्यावसायिक सफलता मापनी :– प्रस्तुत अध्ययन में शोधार्थी, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों की व्यावसायिक सफलता जिसके अन्तर्गत व्यावसायिक समायोजन, व्यावसायिक सन्तुष्टि, अनुकूलित वातावरण, वेतन, व सन्तुलित कार्यभार, आयामों का मापन करने हेतु स्व–निर्मित प्रश्नावली का निमार्ण करेगी ।

3 व्यावसाय आत्म–सम्प्रत्यय मापनी :– प्रस्तुत अध्ययन में शोधार्थी ने विभिन्न आत्मसम्प्रत्यय मापनी का अध्ययन किया परन्तु व्यावसायिक सम्बन्धित प्रमाणित आत्म सम्प्रत्यय मापनी उपलब्ध न होने के कारण शोधार्थी द्वारा स्व–निर्मित प्रश्नावली का निर्माण किया जाएगा।

1.10.0 परिसीमांकन

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा निम्नलिखित परिसीमांकन किया जाएगा–

1. प्रस्तुत शोध अध्ययन में, एम.एस.एम.ई. विकास संस्थान, आगरा व दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीटयूट (डीम्ड विश्वविद्यालय) दयालबाग, आगरा से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों को ही सम्मिलित किया जाएगा।
2. प्रस्तुत शोध अध्ययन आगरा की परिधि तक परिसीमांकित किया जाएगा।
3. प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु कुल 400 प्रशिक्षणार्थियों को जिसमें 200 पुरूष व 200 महिला प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जाएगा।

1.11.0 अध्ययन हेतु प्रयुक्त सांख्यिकीय प्रविधियाँ

एकत्रित प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु प्रदत्तों की प्रकृति के अनुसार वर्णात्मक एवं निष्कर्षात्मक सांख्यिकी प्रविधियों का प्रयोग किया जाएगा, जिसके अन्तर्गत प्रमुख सांख्यिकीय प्रविधियाँ निम्नलिखित है–

- **मध्यमान**
- **प्रमाणिक विचलन**
- **चतुर्थांक विचलन**
- **क्रान्तिक अनुपात**
- **स्वाट विश्लेषण (SWOT ANALYSIS)**
- **प्रतिशत**
- **आलेख प्रस्तुतीकरण**

1.12.0 शैक्षिक निहितार्थ

1. इस शोध अध्ययन के द्वारा व्यावसायिक पाठयक्रम, पुस्तकों की सूची, शिक्षण, प्रशिक्षण विधियों, प्रशासकीय प्रक्रियाओं, निर्देशन तथा सेवाओं में सुधार किया जा सकेगा।
2. इस शोध अध्ययन के द्वारा व्यावसाय चुनाव या पाठयक्रम के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाऐं प्राप्त हो सकेगी।
3. इस शोध अध्ययन के द्वारा शिक्षण में, प्रशिक्षण में आने वाली कमियों एवं खामियों में सुधारात्मक परिवर्तन किया जा सकेगा।
4. इस शोध अध्ययन के निष्कर्षों से प्राप्त परीणामों का सामान्यीकरण करके शैक्षिक एवं व्यावसायिक नीति को भी विकसित करने में सहायता प्राप्त होगी।
5. इसके द्वारा शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं को पृष्ठपोषण भी दिया जा सकेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

एनुअल रिपोर्ट (2014–15), मिनिस्टरी ऑफ माइक्रो स्मॉल एण्ड मीडियम एन्टरप्राइस, www.msme.gov.in.

कार्टर,वी.गुड (1954) , मैथडलोजी ऑफ एजुकेशन रिसर्च, एप्लीटेन सेन्चुरी, न्यूयार्क ।

कॉल, लोकेश (2004), शैक्षिक अनुसंधान की कार्य प्रणाली, विकास पब्लिशिंग हाउस, प्रा0लि0।

कपिल, एच. के. (1992), शैक्षिक सांख्यिकी , प्रथम संस्करण हरप्रसाद भार्गव, पुस्तक प्रकाशन, आगरा।

कात्याल, आशु एवं विट्से एक्सविअर (2015), ए स्टडी आन एम.एस.एम.ई. रोल इन प्रोपलिंग इकॉनोमिक डवलपमेन्ट ऑफ करेन्ट एच आर इशु इन एम.एस.एम.ई. इन इण्डिया, इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ साइन्टिफिक एण्ड रिसर्च पब्लिकेशन, वोल्यूम न. 5, आईएसएसएनः 2250–3153।

कुमार, डी. श्रीनिवास एवं अन्य (2013), सस्टेनेबल ट्रेन्डस एण्ड पोलिसी ऑफ एम.एस.एम.ई. इन इकॉनोमिक डवलपमेन्ट इन इण्डिया : एन इम्पेरिकल स्टडी, इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेन्ट बिजनिस रिसर्च, वोल्यूम न. 3, आईएसएसएनः 2330–9519

कुमार, एन. बी. गुगलोथ, एस. (2012), माइक्रो स्मॉल एण्ड मीडियम एन्टरप्राइसिस इन द 21 सेन्चुरी, जेडईएनआईटीएच इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ बिजनिस इकॉनोमिक्स एण्ड मेनेजमेन्ट रिसर्च वोल्यूम न. 2 (5) 23–38

गैरिट,हेनरी, ई. (1986), 'स्टेटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी एण्ड एजुकेशन, लीगमेन्स

ग्रीन एण्ड कम्पनी , न्यूयार्क।

गुड,बार एवं स्केट्स (1966), 'मैथडलोजी ऑफ रिसर्च, साइकोलॉजी एण्ड सोशलॉजी, सेन्चुरी कफट्स इडक, न्यूयार्क।

गिलअर्ड, जी.पी.(1967), जर्नल साइक्लोजी.डी वन नोस्टर्ड कम्पनी आईएनसी।

गर्ग, ईशु व वालिया, सुरज (2012), एम.एस.एम.ई इम्प्रुवमेन्ट इन नार्थ इण्डियाः स्टेटस एण्ड परफोरमेन्स, इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ लेटेस्ट ट्रेन्ड इन इजिनियरिंग एण्ड टैक्नोलोजी, वोल्यूम न. 1, आईएसएसएनः 2278–621×

ड़ांगी, नेहा एवं रीतिका (2014), वुमेन इन्टर्नशिप ग्रोथ एण्ड एम.एस.एम.ई. इन इण्डिया, इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ एडवान्सड रिसर्च इन कम्प्यूटर साईन्स एण्ड मेनेजमेन्ट स्टडी वोल्यूम न. 2, आईएसएसएनः 2321–7782।

जयन, वी. के. (2013), वुमेन इन्टरप्रीन्योशिप इन एम.एस.एम.ई. (विद् स्पेशल रिफ्रेन्स टू कोयम्बटूर सिटी) इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ एडवान्सड रिसर्च, 1 (4) 321–325

जोशी, धर्मकीर्ती, व अन्य (2010), स्किलिंग इण्डिया : द बिलिसन पीपुल्स चैलेन्ज, **सीआरआईएसआईएल– सेन्टर फॉर इकोनोमिक्स मुम्बई–400076**

टेक्सन, ग्वेंडोलिन आर. (2004) ''रीव्यू ऑफ एगजिस्टिंग पोलिसी अफेक्टिंग माइक्रो स्मॉल एण्ड मीडियम एन्टरप्राइस इन फिलिपिन्स, पब्लिशिग–दा स्मॉल एण्ड मिडियम एन्टरप्राइज डवलपमेन्ट फॉर सस्टेनेबल एमप्लोयमेंन्ट प्रोग्रेम, जर्मन डवलपमेन्ट सेन्टर।

दास, सुरत कुमार (2014) ''ग्रोथ एण्ड प्रोस्पेक्ट आफ एम.एस.एम.ई. इन ओडिशाः एन एनालिटिकल एप्रोच, कॉलेज ऑफ ऐजूकेशन एण्ड टैक्नोलजी, भुवनेश्वर।

दीक्षित, ए एवं पांडेय,ए.के. (2011), एम.एस.एम.ई एण्ड इकॉनोमिक ग्रोथ इन इण्डिया : कोइनटीग्रेशन ऐनालिसिस, जर्नल ऑफ फाइनेनशियल इकोनोमिक्स, वोल्यूम न. 9 पीपी. 41–59

पाण्डेय, के.पी. (1999), शैक्षिक अनुसंधान, विश्वविद्यालय प्रकाशन ,वाराणसी।

मिश्रा,मंजू . (2007), शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन, ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, ।

मंगल,एस.के. (2002), शिक्षा मनोविज्ञान, पीएच.डी. लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, ।

वीना (2015), रोल आफ डवलपमेन्ट इन्स्टीट्यूट इन द इस्टेब्लीस्मेन्ट ऑफ माइक्रो स्मॉल एण्ड

मीडियम एन्टरप्राइस : अ केस स्टडी ऑफ भवानी हरियाणा, अभिनव इन्टरनेशनल मेन्थली रेफर्ड जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेनेजमेन्ट एण्ड टैक्नोलजी, वोल्यूम न. 4, आईएसएसएनः 2320–0073।

वैंकटेश, सुधा. एवं क्रिश्नावेनी, मुथैया (2012), एम.एस.एम.ई इन इण्डिया : इनपोटेन्स एण्ड कॉन्ट्रिब्यूशन, एशियन रिसर्च जर्नल ऑफ मेनेजमेन्ट, आईएसएसएनः 2229–3795

सिद्धू ,के. एस. (1987), 'मैथडलोजी ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन', नई दिल्ली इण्टरलिंग पब्लिशर्स , नई दिल्ली।

सिंह एवं रैना (2013), वुमेन एन्टरप्रीन्योर इन माइक्रो स्मॉल एण्ड मीडियम एन्टरप्राईज, इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ मेनेजमेन्ट एण्ड सोशल साइन्स रिसर्च . 2 (8) 4–8

सुब्रमण्यम,पी. एवं रेड्डी,बी.आर. (2012), माइक्रो स्मॉल एण्ड मिडियम एन्टरप्राइजिस प्रजेन्टिग एन ओवरव्यू , वीएसआरडी इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ बिजनिस एण्ड मेनेजमेन्ट, वोल्यूम न. 9 532–537 ।

सिंह, आर. वर्मा,ओ.पी. व अन्य (2012), स्मॉल स्किल इन्ड्रस्ट्रीः एन इंजन ऑफ ग्रोथ, जीनथ इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ बिजनिस इकॉनोमिक्स एण्ड मेनेजमेन्ट रिसर्च वोल्यूम न. 2 http://www.zenithresearch.org.in .

शर्मा, आर. ए. (2001), शिक्षा अनुसंधान, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ।

शर्मा, रूपाली व ज़िया अफरोज (2014), ''ग्रोथ एण्ड परफोरमेन्स ऑफ एम.एस.एम.ई. इन प्रजेन्ट सिनेरियो फॉर द डवलपमेन्ट ऑफ इण्डिया, इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ इन्टरडिसिप्लेनरी एण्ड मल्टीडिसिप्लेनरी स्टडीज वोल्यूम न. 1, आईएसएसएनः 2348–0343।

श्रीवास्तव, डी.एन. (1995), "आधुनिक असमान्य मनोविज्ञान", आठवाँ संस्करण साहित्य प्रकाशक, आगरा

शर्मा, रूपाली व ज़िया अफरोज (2014), ''ग्रोथ एण्ड परफोरमेन्स ऑफ एम.एस.एम.ई. इन प्रजेन्ट सिनेरियो फॉर द डवलपमेन्ट ऑफ इण्डिया, इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ इन्टरडिसिप्लेनरी एण्ड मल्टीडिसिप्लेनरी स्टडीज वोल्यूम न. 1, आईएसएसएनः 2348–0343।

दयालबाग एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट : http://www.dei.ac.in/

http://www.dei.ac.in/dei/files/events/DEI_Connect.pdf

www.livehindustan.com 8 सितम्बर 2015, आगरा, पांच प्रदेश,18 संस्करण, अंक 211।

एजूकेशन कमीशन एण्ड कमीटीज इन रेट्रोस्पेक्ट :

http://www.teindia.nic.in/mhrd/50yrsedu/g/W/16/0W160301.htm